बरौद कोयला खान हेतु हाल रोड के निर्माण में भ्रष्टाचार

2796. **श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस०ई०सी०एल० की बरौद कोयला खान के लिए हाल रोड के निर्माण में भ्रष्टाचार संबंधी कोई गंभीर शिकायत समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों की जांच कराने के संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है, और

(ग) जांच कार्य में अब तक हुई प्रगति एवं उस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांच पूर्ण कर ली गई है तथा इस मामले में अनियमितताओं में अंतर्ग्रस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध बड़ी दण्डात्मक कार्रवाही आरम्भ कर दी गई है।

शहरी उपभोक्ता सहकारी भंडारों के लिए सहायता

2797. **श्री रहसबिहारी बारिक: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीयकृत प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के माध्यम से शहरी उपभोक्ता सहकारी भंडारों का विकास किया जा रहा है;

(ख) क्या केंद्र द्वारा राज्य स्तर पर उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के विकास और विस्तार के लिये भी धनराशि प्रदान किये जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस दिशा में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पंजाब और आंध्र प्रदेश में धान के खरीद मूल्य में अन्तर

2798. **श्रीमती रेणुका चौधरी: क्या खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब और आंध्र प्रदेश में धान के खरीद मूल्य में क्या अन्तर है;

(ख) यदि कोई अन्तर है, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लगाये गये उपकर पर यथोचित रूप में विचार करते हुए सरकार आंध्र प्रदेश में धान के खरीद मूल्य में वृद्धि करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) ऐसा कोई अन्तर नहीं है। किसानों को अदा किया जाने वाला वसूली मूल्य पूरे देश में एक-समान है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Revised New Licensing Policy for Sugar Mills

2799. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed and revised a new licensing policy for sugar mills;

(b) if so, the salient features thereof;

(c) whether a number of new sugar mill icences have been issued this year; and

(e) if so, the State-wise details thereof?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFARIS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) and (b) There is no change in the licensing policy for establishment of new sugar mills and expansion in the existing sugar units.

(c) and (d) 44 letters of intent have been issued for establishment of new sugar factories by the Ministry of Industry during the current 1995-96